

हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, नियम तोड़ने पर लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी

सस्ते पैकेज दिखाकर मरीजों से छिपे शुल्क नहीं वसूल सकेंगे अस्पताल

■ चिकित्सा सेवा व्यापार नहीं, भरोसे का क्षेत्र, स्वास्थ्य नीतियों में व्यापार नहीं, करुणा और पारदर्शिता सर्वोपरि होनी चाहिए

■ हाईकोर्ट ने हरियाणा स्वास्थ्य विभाग को तीन महीने में जांच पूरी कर कार्रवाई रिपोर्ट देने के निर्देश दिए

हरिभूमि ब्यूरो ►► चंडीगढ़



■ मरीज की भाषा में देनी होगी इलाज की पूरी जानकारी, लागत, पैकेज और संभावित अतिरिक्त खर्च स्पष्ट रूप से समझाना होगा

सरकारी पैनल में शामिल अस्पताल अब मरीजों को कम कीमत वाले आकर्षक पैकेज दिखाकर बाद में इलाज के जरूरी हिस्सों के नाम पर अतिरिक्त और छिपे हुए बिल नहीं थमा सकेंगे। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने इस प्रवृत्ति पर कड़ा प्रहार करते हुए स्पष्ट किया कि चिकित्सा सेवा कोई व्यावसायिक जाल नहीं, बल्कि भरोसे और पारदर्शिता का क्षेत्र है। अदालत ने कहा कि मरीजों को प्रारंभिक पैकेज के नाम पर लुभाना और बाद में आवश्यक प्रक्रियाओं को अलग-अलग दिखाकर बिल बढ़ाना न केवल नीति का उल्लंघन है, बल्कि

हाई कोर्ट ने विशेष रूप से इस बात पर विता जताई कि कई अस्पताल मरीजों या उनके परिजनों से बिना समुचित जानकारी दिए केवल छपे हुए फॉर्म पर हस्ताक्षर करवा लेते हैं। अदालत ने कहा कि इलाज की लागत, पैकेज में शामिल सुविधाएं और संभावित अतिरिक्त प्रक्रियाओं की जानकारी मरीज या उसके परिजन को उनकी समझ की भाषा में स्पष्ट रूप से दी जानी चाहिए। केवल औपचारिक हस्ताक्षर लेकर जिम्मेदारी पूरी मान लेना स्वीकार्य नहीं होगा। जस्टिस बराड़ ने अपने आदेश में बोलकर कहा कि "इलाज की लागत मरीज या उसके निकट संबंधी को ऐसी भाषा में समझाई जाए, जिसे वे समझते हों। केवल साइक्लोस्टाइल्ड प्रोफार्मा पर हस्ताक्षर करवाने की प्रथा पर्याप्त नहीं है। मरीजों को पहले कम पैकेज दिखाकर आकर्षित करना और बाद में उपचार के आवश्यक हिस्सों के लिए अलग से शुल्क वसूलना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

कल्याणकारी राज्य की भावना के भी विपरीत है। जस्टिस हरप्रत सिंह बराड़ ने अपने विस्तृत आदेश में हरियाणा के स्वास्थ्य महानिदेशक को निर्देश दिया कि राज्य के सभी पैनल अस्पतालों की पैकेज दरों की व्यक्तिगत रूप से अथवा संबंधित सिविल सर्जन के माध्यम से जांच

कराई जाए। यदि कोई अस्पताल नीति के विरुद्ध जाकर मरीजों से अनुचित वसूली करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, जिसमें लाइसेंस रद्द करना भी शामिल हो सकता है। अदालत ने पूरी प्रक्रिया तीन महीने में पूरी कर अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई चिकित्सा प्रक्रिया जीवन बचाने के लिए आवश्यक और आपातकालीन थी, तो उसका खर्च प्रतिपूर्ति योग्य होगा। राज्य यह कहकर जिम्मेदारी से नहीं बच सकता कि मरीज ने पारंपरिक प्रक्रिया नहीं अपनाई। कोर्ट ने कहा कि चिकित्सा नीति में करुणा सर्वोपरि होनी चाहिए, व्यापारिक लाभ नहीं। अपने आदेश के अंत में हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि चिकित्सा और चिकित्सकीय सहायता एक "उदात्त क्षेत्र" है, इसलिए राज्य की नीतियों में भी वही उदात्तता दिखाई देनी चाहिए। यदि नीति में करुणा की जगह व्यापार हावी हो जाए, तो वह कल्याणकारी नीति नहीं रहे जाती। यह फैसला अब मरीजों के अधिकार, पारदर्शी स्वास्थ्य व्यवस्था और अस्पतालों की जवाबदेही को लेकर एक बड़ी न्यायिक चेतावनी माना जा रहा है।

दिशा की बैठक में मंत्री गुर्जर नगर निगम अधिकारियों से बोले फरीदाबाद में भ्रष्टाचार किया तो हथकड़ी लगवा दूंगा, तुम्हें कीड़े पड़ेंगे

हरिभूमि न्यूज ►► फरीदाबाद

केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने नगर निगम के चीफ इंजीनियर, एक्सइन समेत कई अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। गुर्जर ने कहा कि यहां से चले जाओ, नहीं तो हथकड़ियां लगवा दूंगा तुम्हें कीड़े पड़ेंगे। अधिकारियों ने लूट का अड्डा बनाया हुआ है। दिशा की मीटिंग में मौजूद विधायक मूलचंद शर्मा ने इन अधिकारियों से कहा कि निगम में भ्रष्टाचार कर रखा है, तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है। कमिश्नर साहब इन्हें हिंदी में समझा दीजिए। दरअसल, कृष्णपाल गुर्जर को नगर निगम में भ्रष्टाचार की शिकायत मिल रही थी। इसी को लेकर मंगलवार



को निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की। मीटिंग में मंत्री ने कहा कि शहर की अधिकारियों ने लूट का अड्डा बना रखा है। ठेकेदारों के जरिए निगम के पैसे की बंदरबॉट हो रही है। इंटरलॉकिंग टाइल और सीवर ढक्कनों में लगातार घंटिया क्वालिटी की सामग्री इस्तेमाल

होने की शिकायत मिल रही है। गुर्जर आज सेक्टर-12 में जिला फरीदाबाद में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए विभिन्न एजेंडों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। इसमें योजनाओं के बजट व्यय, लाभार्थियों तक पहुंच, जमीनी प्रभाव और पारदर्शिता को प्रमुखता से लिया गया। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि निगम में पेड़ों के नाम पर लाखों के बिल बनाए जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर कोई पेड़ नहीं मिलता है। यहां से 10-10 करोड़ रुपये के पेड़ गायब हैं। माल ये लोग खाते हैं, बदनामी हमारी होती है।

14 मई को 13 जिलों में होगी राज्यव्यापी बाढ़ मॉक ड्रिल

■ बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के लिए सिस्टम, संसाधनों और सामुदायिक भागीदारी को किया जाएगा मजबूत

और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य विभिन्न विभागों, एजेंसियों और समुदायों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर आपदा की स्थिति में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तीयकृत डॉ. सुमिता मिश्रा ने मॉक ड्रिल से पहले आयोजित टेबल टॉप एक्सरसाइज और ओरिएंटेशन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार अब केवल आपदा आने के बाद प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले से तैयारी और रोकथाम पर विशेष ध्यान दे रही है। हरियाणा की भविष्य में बाढ़ जैसी आपात स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता को मजबूत करने की एक व्यावहारिक पहल है।

हड़ताली सफाई कर्मचारियों के साथ आज हो सकती है वार्ता

हरिभूमि ब्यूरो ►► चंडीगढ़

प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से हालात बिगड़ने लगे हैं। सड़कों पर 12 हजार टन से अधिक कचरा पड़ा हुआ है। शहरों में स्वच्छ सर्वेक्षण का कार्य अटक गया है। हालात बिगड़ने पर अब सरकार की नौद टूटी है। अब बुधवार को चंडीगढ़ में सुबह 11 बजे हड़ताली कर्मचारियों के साथ बैठक होगी। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश शास्त्री ने बताया कि शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय के अधिकारियों ने वार्ता का समय तय किया है। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में होने वाली इस बैठक में निकाय मंत्री विपुल

गोयल भी शामिल रहेंगे। शास्त्री ने कहा कि हड़ताल दमकल कर्मियों की मांगें मानने पर ही समाप्त होगी। निकाय के सफाई कर्मचारियों की जो भी लंबित मांगें हैं उन्हें पूरा करना होगा। शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय के आयुक्त एवं सचिव अशोक मीणा ने बताया कि हरियाणा नगर पालिका कर्मचारी संघ के साथ वार्ता के लिए बुधवार का समय निर्धारित किया है। उम्मीद है कि निकाय मंत्री की मौजूदगी में होने वाली इस बैठक में सकारात्मक परिणाम आएंगे। वहीं दूसरी तरफ निगमों के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के समर्थन में करीब 10500 ग्रामीण सफाई कर्मी भी आ गए हैं।

एसिड अटैक पीड़ित, विधवा, स्वयं सहायता समूह व एकल माताओं को प्राथमिकता प्रदेश में 4 हजार नए राशन डिपो जल्द, 33% महिलाओं को मिलेगा रोजगार का अवसर

■ महिला आवेदक के लिए 12वीं पास, कंप्यूटर ज्ञान व 21-45 वर्ष आयु सीमा अनिवार्य

■ चयन 'रोस्टर सिस्टम' व सरल पोर्टल के जरिए ऑनलाइन पारदर्शी प्रक्रिया से होगा

योगेंद्र शर्मा ►► चंडीगढ़

दिए जाएंगे। इससे महिलाओं को रोजगार के साथ-साथ आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि इस संबंध में विभागीय प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने गैस सिलेंडर ब्लैक (कालाबाजारी) की खबरों का खंडन करते हुए इसे विपक्ष द्वारा फैलाई गई अफवाह बताया और कहा कि इस तरह की गतिविधियां में शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री ने बताया कि 4 हजार नए राशन डिपो का प्रस्ताव तैयार है और

जल्द ही आवंटन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 33 प्रतिशत आरक्षण के तहत महिलाओं को डिपो दिए जाएंगे, जिससे उनका आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित होगा। सरकार ने राशन डिपो (उचित मूल्य की दुकानों) के लाइसेंस आवंटन में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। नए नियमों के अनुसार, हर ब्लॉक को रोस्टर प्रणाली लागू होगी, जिसमें हर तीसरी रिक्ति महिला के लिए आरक्षित होगी।

300 की बजाय 500 राशन कार्डों पर नया डिपो लाइसेंस एसिड अटैक पीड़ित, विधवा, तलाक़सूत्रा, एकल माताएं और स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी। महिला आवेदक के लिए 12वीं पास होगा, कंप्यूटर ज्ञान और आयु 21 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदक को संबंधित क्षेत्र का निवासी होना और परिवार पंजीकृत पत्र आवश्यक होगा। नए प्रावधानों के तहत अब एक डिपो 300 की बजाय 500 राशन कार्डों पर आवंटित होगा। अच्छे प्रदर्शन करने वाले डिपो संचालक 65 वर्ष तक कार्य कर सकेंगे और लाइसेंस 5 साल तक बढ़ाया जा सकेगा।

पैरा एथलीट विनोद कुमार को नहीं मिलेगा विनेश फोगाट जैसा लाभ

हाईकोर्ट ने 4 करोड़ की मांग ठुकराई

चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पैरा एथलीट विनोद कुमार की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने पहलवान विनेश फोगाट की तरह चार करोड़ रुपये और अन्य वित्तीय लाभ देने की मांग की थी। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि वर्ष 2024 की घटनाओं के आधार पर वर्ष 2020 के मामले में समानता का दावा नहीं किया जा सकता। जस्टिस जगमोहन बंसल ने कहा कि यदि ऐसी मांगों को स्वीकार किया गया तो भविष्य में हर खिलाड़ी बाद की नीतियों और बढ़ी हुई पुरस्कार राशियों के आधार पर समान लाभ मांगने लगेगा, जिससे सरकारी नीतियों का संचालन कठिन हो जाएगा। याचिका में विनोद कुमार ने बताया कि उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में एफ-52 श्रेणी में कांस्य पदक जीता था, लेकिन बाद में विशेषज्ञ समिति ने उन्हें अयोग्य घोषित कर पदक वापस ले लिया।

कालेज कैडर असिस्टेंट प्रोफेसर 'अंग्रेजी' भर्ती रद्द

चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार और एचपीएससी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर (अंग्रेजी) भर्ती प्रक्रिया को यूजीसी नियमों के खिलाफ मानते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 2 अगस्त 2024 के विज्ञापन संख्या 48/2024 के तहत की जा रही चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया जस्टिस त्रिभुवन बढिया की एकलपीठ ने कहा कि यूजीसी 2018 रेगुलेशन के अनुसार चयन प्रक्रिया में अकादमिक स्कोर आधारित शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू अनिवार्य हैं, लेकिन हरियाणा ने स्क्रीनिंग टेस्ट और सबजेक्ट वॉलेज टेस्ट जोड़कर मूल दांचे में बदलाव किया, जो नियमों के विपरीत है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार यूजीसी के न्यूनतम मानकों में बदलाव नहीं कर सकती। इस फैसले से स्क्रीनिंग और सबजेक्ट टेस्ट पास कर चुके अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है।

50 शैलो ट्यूबवेल के लिए 621.90 लाख मंजूर

■ नूंह जिले के जलभराव प्रभावित गांवों को मिलेगा बड़ा लाभ

■ हजारों एकड़ भूमि फिर होगी खेती योग्य, भूजल विकास एवं सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में सरकार का महत्वपूर्ण कदम

हरिभूमि ब्यूरो ►► चंडीगढ़

मुख्यमंत्री नयब सिंह सैनी ने सिंचाई व्यवस्था और भूजल संसाधनों के विकास को बढ़ावा देने के लिए बड़ा निर्णय लेते हुए गुरुग्राम केनाला राजस्थान लिंक केनाला के साथ 50 शैलो ट्यूबवेल लगाने हेतु 621.90 लाख रुपये की प्रशासनिक मंजूरी

प्रदान की है। यह परियोजना "ग्राउंड वॉटर डेवलपमेंट एवं अन्य संबंधित गतिविधियां" योजना के तहत क्रियान्वित की जाएगी, जिसकी निगरानी वाईडब्ल्यूएस फरीदाबाद के चीफ इंजीनियर व अधीक्षण अभियंता द्वारा की जाएगी। इस योजना से नूंह जिले के 15 से अधिक जलभराव प्रभावित गांवों को राहत

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 Cr.P.C. देखिए

मेरे समक्ष परियाद किया गया है कि अभियुक्त राहुल पुत्र धरमबीर निवासी मकान संख्या 922, गंगल कलां, थाना कुंडली, सोनीपत, हरियाणा ने **प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 203/2023 धारा 498ए/406/34 भा.दं.सं., थाना बवाना, दिल्ली** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए निरपेक्षारी वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त राहुल मिल नहीं रहा है और मुझे समाधान प्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त राहुल फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)। इसके खिलाफ माननीय अदालत द्वारा **धारा 82 Cr. P.C.** की कार्यवाही जारी हो चुकी है। इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि **प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 203/2023 धारा 498ए/406/34 भा.दं.सं., थाना बवाना, दिल्ली** के उक्त अभियुक्त राहुल से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष उक्त परिवार का उत्तर देने के लिए **21.07.2026** को हाजिर हो।
आदेशानुसार: सुश्री सायना दहल, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, उतर महिला न्यायालय-01, कमरा संख्या 102, प्रथम मंजिल, रोहिणी कोर्ट, दिल्ली।

DP/6194/ON/2026

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 19.05.2025 को जिला कारागार रोहतक के बंदियों द्वारा बचाई गई रोटियों सब्जी तथा दाल को उठाने के लिए टेकर देने हेतु ई-आव्हन के माध्यम से बोली करवाई जाएगी जिसके लिए आप अपना आवेदन **eauction.gov.in** पर जाकर कर दिनांक 12.05.2026 से दिनांक 17.05.2026 तक कर सकते हैं। टैंडर के सम्बंध मे कोई भी बोली दाता ई-आव्हन पर जाकर उपरोक्त टैंण्डर को एक वर्ष 01.06.2026 से 31.05.2027 तक ले सकते हैं।
टैंडर की शर्तें निम्नलिखित है।
1. स्वीकृत ठेकेदार को बची हुई रोटियो व दाल सब्जी सप्ताह में दो बार जरूर उठानी होगी।
2. स्वीकृत ठेकेदार की अवधि एक वर्ष के लिए होगी।
3. नीलामी में भाग लेने के लिए बोलीदाता को 50000 (पचास हजार रूपए) धरोहर राशि जमा करवानी होगी।
4. अधीक्षक जिला कारागार रोहतक के पास बोली स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने का अधिकार होगा व इस कार्य में उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद का निपटारा स्थानीय न्यायालय में होगा।
5. ठेकेदार जेल के अन्दर किसी भी बंदी से किसी प्रकार का लेनदेन या व्यवहार नहीं करेगा और ना ही किसी प्रकार का ऐसा कार्य करेगा जो जेल नियमों के विरुद्ध हो। ऐसा करने पर उसे नियमों के अनुसार दण्डित किया जा सकता है।
6. रोटी व दाल सब्जी उठाने के लिए स्वीकृत ठेकेदार को अपने वाहन का प्रयोग करना पड़ेगा।
7. यदि स्वीकृत ठेकेदार उपरोक्त शर्तों को तोड़ता है तो इसकी धरोहर राशि जल्न करके ठेके को समाप्त कर दिया जाएगा।
पीआरडीएच-1277/11/112/2027/45076/88/6 दि. 12.05.26

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, फतेहाबाद

गुमशुदा की तलाश

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है मनदीप पुत्र बलजीत निवासी गाँव गोरखपुर, थाना भूना, जिला फतेहाबाद, दिनांक 18.12.2025 को अपने घर से बिना बताए कहीं चला गया है। परिजनों व पुलिस द्वारा अब तक की गई तलाश के बावजूद उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। गुमशुदा लडके का हुलिया निम्नलिखित है: नाम: मनदीप उम्र: लगभग 25 वर्ष कद: लगभग 5 फीट 7 इंच रंग: गेहुआ चेहरा: गोला पहनावा: सफेद रंग की पैंट-शर्ट व पैरों में जूते पहने हुए है। जिस किसी सज्जन को उपरोक्त लडके के संबंध में कोई सूचना प्राप्त हो, वह कृपया तुरंत नीचे दिए गए संपर्क सूत्रों पर सूचित करें: संपर्क करें: थाना भुना मोबाइल नं.: प्रबन्धक अफसर थाना भुना 88140-11710, अनुसंधान कर्ता 9416529929 या नजदीकी पुलिस स्टेशन में जानकारी दें। आपकी दो गई सूचना गुप्त रखी जाएगी। पीआरडीएच-1084/11/4800/2027/45077/88/6 दि. 12.05.2026

महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक

(हरियाणा अधिनियम सं. XXV ऑक्ट 1975 के तहत स्थापित) एनएएससी द्वारा प्रमाणित 'ए+' ग्रेड विश्वविद्यालय

शैक्षणिक वर्ष 2026-27 हेतु प्रवेश सूचना

(विज्ञा. सं. पीआर-03 ऑफ 2026)

शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु विश्वविद्यालय अध्यापन विभागों/संस्थानों/केंद्रों, म.द. विश्वविद्यालय, रोहतक और एमडीयू-सीपीएस, गुरुग्राम द्वारा संचालित किए जा रहे भारतीय और विदेशी नागरिकों के लिए 4-वर्षीय अंडर-ग्रेजुएट प्रोग्राम्स (एनईपी-2020 के अनुरूप), 5-वर्षीय एकीकृत प्रोग्राम्स, 5-वर्षीय एलएल.बी. प्रोग्राम और 4-वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) के लिए प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन जमा हेतु पोर्टल का खुलना : 11.05.2026 भारतीय नागरिकों के लिए आवेदन प्रपत्र जमा हेतु अन्तिम तिथि : 26.05.2026 विदेशी नागरिकों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र जमा हेतु अन्तिम तिथि : 20.06.2026 पात्रता शर्तों, सीटों की संख्या, शुल्क और अन्य विवरण हेतु, कृपया विश्वविद्यालय वेबसाइट अर्थात www.mdu.ac.in पर उपलब्ध 2026-27 की विवरणिका ध्यानपूर्वक पढ़ें। परिवर्तन/अद्यतन, यदि कोई हो, विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अधिसूचित किये जाएंगे। संवाद-1235/11/172/2027/45084/सी/88/6 दि. 12.05.26 रजिस्ट्रार

उत्तर रेलवे

खुली निविदा सूचना संख्या-ETRU-T-02-2026-27

वॉरि. मंडल विद्युत अभियंता/क.वि./उत्तर रेलवे, अम्बाला छावनी द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्यों के लिए ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदायें आमंत्रित करते हैं। इन निविदाओं को प्रत्येक कार्य के आगे दर्शाई गई तिथि को 15:00 बजे तक www.ireps.gov.in पर अपलोड किया जा सकता। इनकी 15:00 बजे के उपरांत तत्काल खोला जायेगा।

क्र.संख्या

कार्य का विवरण

निविदा बंद/खुलने की तिथि

लगभग लागत

धरोहर राशि

कार्य पूरा करने की अवधि

बैधता अवधि

टेण्डर फॉर्म की कीमत

1 ETRU-T-02-2026-27 25 केबी एसी 50 हर्ट्स ओएचई का डिजाइन, आपूर्ति, परीक्षण और कमीशनिंग के संबंध में अंबाला मंडल में 20000 से अधिक टोवीयु वाले मानवयुक्त गैर-इंटरलॉकड 23 लू-जिग गेटों की इंटरलॉकिंग हेतु कार्य। 03.06.2026 3,50,52,121.22/- 7,01,100/- 09 महीने 60 दिन Downloading through IREPS portal- NILE (₹ 10,000/- /- S.DEE/TRD/JUMB ऑफिस से हार्ड कॉपी के लिए)

1. निविदाकार को सभी जरूरी योग्यता दस्तावेज एवं PAN/GSTIN की Scanned Copies IREPS पोर्टल पर अपलोड करनी है। 2. निविदाकार के पास ई-निविदा में भाग लेने के लिए क्लैस-III Digital Signature Certificate होनी चाहिए। 3. कार्य में GST, BOCWW, Income Tax एवं नियमानुसार आवश्यक टेक्स लागू होंगे। 4. कार्य में सिमिलर नेचर कंडीशन लागू हैं एवं इस प्रकार है: "Design, supply, erection, testing & commissioning of 50Hz, single phase 25 KV AC OHE". 5. टेंडर डॉक्यूमेंट एवं निविदा सूचना की विस्तृत जानकारी के लिए रेलवे वेबसाइट www.ireps.gov.in पर जाये। संख्या: ETRU-T-02-2026-27 दिनांक: 12.05.2026 1584/2026

चाहकों की सेवा में मुक्तक के साथ

2	9	8	3	5	6	1	7	4
4	5	3	2	1	7	9	8	6
7	1	6	4	8	9	2	5	3
8	2	5	6	9	1	3	4	7
3	6	4	7	2	5	8	1	9
1	7	9	8	3	4	5	6	2
5	4	1	9	7	2	6	3	8
6	3	2	1	4	8	7	9	5
9	8	7	5	6	3	4	2	1

गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह....सरमा ने सीएम पद की ली शपथ

असम में भाजपा ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की

एजेन्सी► गुवाहाटी

असम में नए मंत्रिमंडल का शपथग्रहण मंगलवार को हुआ। भाजपा नेता हिमंत बिस्व सरमा ने लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उनके साथ 4 और नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। अन्य जिन नेताओं ने शपथग्रहण में हिस्सा लिया, उनमें भाजपा की सहयोगी पार्टी- बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट (बीपीएफ) और असम गण परिषद (एजीपी) के नेता भी शामिल रहे।

इसके अलावा हिमंत कैबिनेट में एक छह बार की महिला विधायक को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। असम में भाजपा ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की है। यह पहली बार नहीं है जब हिमंत ने असम में भाजपा का झंडा बुलंद करने की जिम्मेदारी संभाली और उसे अंजाम तक पहुंचाया। वह ये काम 2016 से ही करते आ रहे हैं। पर, उन्हें मुख्यमंत्री बनने का पहला मौका 2021 में मिला था।



अतुल सबसे अजीर
अतुल बोरा असम के एक प्रमुख नेता और असम गण परिषद (एजीपी) के अध्यक्ष हैं। उनका जन्म 7 अप्रैल 1960 को असम के गोलाघाट जिले के बोराही गांव में हुआ था। बोरा ने 1995 में असम गण परिषद (एजीपी) के कार्यकर्ता के रूप में मुख्यधारा की राजनीति में प्रवेश किया। वे पहली बार 1996 में गोलाघाट से विधायक चुने गए। 2016 से लगातार बोकाखाट निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने सर्वानंद सोनोवाल और सरमा दोनों के मंत्रिमंडलों में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया है। उनके चुनावी हलफनामे के अनुसार, उनकी कुल घोषित संपत्ति लगभग 6.87 करोड़ है।

चरण बोरो
चरण बोरो असम के राजनीतिक दल बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट पार्टी के कद्दावर नेता हैं। वे मजबूत निर्वाचन क्षेत्र से लगातार तीसरी बार विधानसभा के लिए चुने गए हैं। उन्होंने पिछली सरकार के मंत्रिमंडल में परिवहन मंत्री के रूप में कार्य किया था। 46 वर्षीय चरण के एक उच्च-शिक्षित नेता हैं; उन्होंने 2003 में गुवाहाटी विश्वविद्यालय से गणित में मास्टर डिग्री हासिल की है।

अर्जुन न्योग असम
अर्जुन न्योग असम भाजपा का प्रमुख महिला चेहरा हैं। वे राज्य की सबसे लंबे समय तक विधायक रहने वाली महिला और असम की पहली महिला वित्त मंत्री होने का गौरव रखती हैं।

रामेश्वर तेली
रामेश्वर तेली असम में भाजपा के प्रमुख नेता हैं। वे विशेष रूप से असम के चाय बागान समुदाय के एक कद्दावर नेता माने जाते हैं। उनका जन्म 14 अगस्त 1970 को असम के दुलियाजान में हुआ था। उनके पिता का नाम बुधु तेली और माता का नाम दुर्लका तेली है। पिता झड़वर थे और तेली का बचपन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा। विश्वरावस्थान में वे स्नेक्स के लिए ब्रेड खरीदने हेतु रस्तालू और फर्न बेचते थे।

असम विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पर संशय

126 सदस्यीय असम असेंबली में इस बार आधिकारिक तौर पर नेता प्रतिपक्ष नहीं हो सकता है। भाजपा और उसके दो क्षेत्रीय सहयोगियों ने मिलकर 102 सीट जीतीं, जबकि विपक्षी गठबंधन केवल 21 सीटों पर सिमट गया। इनमें कांग्रेस को 19 और राहुजोर दल को 2 सीटें मिली हैं। बाकी 3 सीटों में से ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 और टीएमसी को 1 सीट मिली, लेकिन ये कांग्रेस-नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं। आम तौर पर किसी विधायक दल को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा पाने के लिए सदन की कुल संख्या का कम-से-कम 10% यानी विस में 13 सीटें चाहिए होती हैं। कांग्रेस के पास 19 सीटें हैं, लेकिन अगर विपक्षी दलों की औपचारिक मान्यता या गठबंधन संरचना को लेकर तकनीकी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई, तो विस में आधिकारिक नेता प्रतिपक्ष का पद खाली रह सकता है।



मादा चीता के साथ शावकों की तस्वीर... एक महीने पहले की

कूनो नेशनल पार्क से आई बुरी खबर 4 चीता शावकों की हुई मौत 11 अप्रैल को हुआ था जन्म

श्यापुर। कूनो नेशनल पार्क से बुरी खबर सामने आई है। यहां पार्क के जंगल में जन्मी मादा चीता केजीपी 12 के चारों शावक मृत पाए गए हैं। मंगलवार की सुबह जब मॉनिटरिंग टीम श्यापुर टेरिटोरियल डिवीजन पहुंची, तब उन्हें डेन साइट (मांद) के पास शावकों के शव मिले। कूनो प्रबंधन के अनुसार शावकों के शव आंशिक रूप से खाए हुए पाए गए हैं। इन शावकों का जन्म 11 अप्रैल 2026 को हुआ था और वे महज एक महीने के थे। मॉनिटरिंग टीम ने 11 मई की शाम को इन्हें अंतिम बार जीवित देखा था।

मांद के पास उनके आंशिक रूप से खाए हुए शव मिले

कूनो प्रबंधन सकते हैं

2 दिन से कूनो नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट चीता को लेकर उत्साह का वातावरण था। 10 मई को मदर्स डे पर मादा चीता व शावकों की शॉर्ट फिल्म जारी की गई थी, फिर 11 मई को सीएम डॉ. मोहन यादव ने बोटसवाना से लाई गई दो मादा चीताओं को बाड़े से खुले जंगल में रिलीज किया था, लेकिन इसके अगले 4 शावकों की मौत की खबर ने कूनो प्रबंधन को सकते में ला दिया है।

फ्लोर टेस्ट से पहले विजय को झटका हाईकोर्ट ने टीवीके विधायक के सदन में जाने पर लगाई रोक

चेन्नई (भाषा)। तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट से पहले विजय को हाईकोर्ट से झटका लगा है। मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को टीवीके विधायक आर श्रीनिवास सेतुपति पर तमिलनाडु विधानसभा में विश्वास मत समेत किसी भी मतदान में हिस्सा लेने पर अंतरिम रोक लगा दी। न्यायमूर्ति एल. विक्टोरिया गौरी और न्यायमूर्ति एन. सैथिलकुमार की अवकाशकालीन पीठ ने द्रमुक उम्मीदवार के. आर. पेरियाकरुपन की याचिका पर यह अंतरिम आदेश पारित किया।

भारत की मेजबानी में कल से होगी ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक

कविता जोशी► नई दिल्ली

पश्चिम-एशिया संकट के बीच भारत की राष्ट्रीय राजधानी ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस सप्ताह 14 से 15 मई तक यह बैठक भारत मंडपम में होगी। जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर करेंगे। लेकिन क्या इस बैठक में ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के विदेश मंत्री शामिल होंगे? हरिभूमि के इस प्रश्न के जवाब में विदेश

2006 में हुआ गठन
गौरतलब है कि ब्रिक्स का गठन वर्ष 2006 में हुआ था। उस वक्त रूस, चीन, भारत और बाजील ने मिलकर इसकी स्थापना की थी।

मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि यह बैठक दो दिवसीय होगी। जिसकी अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री कर रहे हैं। ईरान और यूएई की तरफ से कौन आएगा? इस लेकर निर्णय संबंधित देशों को करना है।

मनाली-लेह राजमार्ग 42 दिन बाद बहाल

प्रशासन जल्द ही जवानों, पर्यटकों व सामान्य वाहनों की आवाजाही शुरू करेगा

बीआरओ के जवानों ने 16 हजार फीट ऊंचे बारालाचा पास से बर्फ हटाई, सभी ने सराहा

10 जनपथ में चल रही मैराथन बैठक

केरल सीएम पर सस्पेंस बरकरार अगले 24 घंटे में फैसला संभव

एजेन्सी► नई दिल्ली

कांग्रेस आलाकमान केरल के मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए दिल्ली में विचार-विमर्श का अंतिम दौर जारी है। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली के 10 जनपथ मैराथन बैठक चल रही हैं। केरल कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और केंद्रीय नेतृत्व से मिल चुके हैं। सूत्रों ने ये भी बताया कि पार्टी अगले 24 घंटों के अंदर अंतिम फैसला ले सकती है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अंतिम चर्चा में भाग लेने के लिए शाम तक दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है, जिसके बाद अंतिम निर्णय पर मोहर लागेगी। फिलहाल केसी वेणुगोपाल इस रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं,

रेस में वेणुगोपाल आगे
बताया जा रहा है कि कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल को फिलहाल इस दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा है। हालांकि, नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी दुविधा ये है कि क्या पार्टी राजनीतिक रूप से इतने महत्वपूर्ण मोड़ पर उन्हें दिल्ली से बाहर भेजने का जोखिम उठा सकती है। वेणुगोपाल संसद के अंदर और संगठन के भीतर दोनों जगह राहुल गांधी के प्रमुख संकटमोचक के रूप में उभरे हैं, जिससे उन्हें विपक्ष के नेता के 'सहायक व्यक्ति' के रूप में मशहूर है।

लेकिन रमेश चैन्नथला को भी एक सुरक्षित और सर्वसम्मत विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है।



सत्यमेव जयते

ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार

ग्रामीण रोज़गार की नई गारंटी

विकसित भारत -

जी राम जी एक्ट

1 जुलाई, 2026 से पूरे देश में लागू

रोज़गार गारंटी अब पहले से हुई बेहतर

रोज़गार की गारंटी और आजीविका विकास के अवसर



125 दिन का विश्वास
पहले जैसा भरोसा, अब और बढ़ा



मज़दूरी का भुगतान अब 15 दिनों के भीतर



जल सुरक्षा एवं जल संबंधी कार्यों को मिलेगा बढ़ावा



आजीविका के अवसरों का होगा विस्तार



गांवों में मज़बूत बुनियादी ढांचे का निर्माण



प्रतिकूल मौसमीय घटनाओं से बचाव की तैयारी



125 दिन की रोज़गार गारंटी
1 जुलाई, 2026 से



रोज़गार से विकसित गांव और विकसित गांव से विकसित राष्ट्र निर्माण

CBC 35101/13/0001/2627

चिंतन नीट परीक्षा की शुचिता पर फिर उठे सवाल

देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी 2026 का रद्द होना केवल एक परीक्षा का स्थगन नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा की शुचिता पर उठा बड़ा सवाल है। हरियाणा के गुरुग्राम, बिहार के नालंदा और राजस्थान के सीकर से सामने आए तथ्यों ने पूरे देश को चौंका दिया। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 300 से अधिक प्रश्न हाथ से लिखे गए एक कथित ‘क्वेश्चन बैंक’ में मिले, जिनमें से करीब 150 सवाल हब्वू नीट परीक्षा में पूछे गए। यह कोई संयोग नहीं हो सकता। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि किसी कोचिंग सामग्री या संभावित प्रश्न बैंक से कुछ प्रश्न मिल जाना सामान्य बात हो सकती है, लेकिन 720 में से लगभग 600 अंकों के प्रश्न एक ही स्रोत से आ जाना सीधे-सीधे संपठित फजीवाड़े की ओर इशारा करता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर देश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली परीक्षा में यह संघं लगी कैसे? एनटीए वर्षों से दावा करता रहा है कि परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, बायोमेट्रिक सत्यापन, जीपीएस ट्रैकिंग, एआई-आधारित मॉनिटरिंग और 5जी जैमर जैसी अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जब परीक्षा से पहले ही कथित प्रश्नपत्र व्हाट्सएप ग्रुपों में घूमने लगे, तो यह तकनीकी दावों की पोल खोल देता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि खतरा परीक्षा केंद्रों पर बैठा छात्र नहीं, बल्कि वह “घर का भेदी” है जो प्रिंटिंग प्रेस, डेटा सिस्टम या एजेंसी के भीतर बैठकर पूरी व्यवस्था को बेच रहा है। नीट परीक्षा का रद्द होना लाखों छात्रों के लिए मानसिक आघात है। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने दो-दो साल तक कोचिंग में दिन-रात मेहनत की, जिन्होंने परिवार की आर्थिक सीमाओं के बावजूद सपनों को जिंदा रखा, आज वे खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। परीक्षा रद्द होने का अर्थ केवल दोबारा परीक्षा देना नहीं होता; इसका मतलब है तनाव, अवसाद, आर्थिक बोझ और भविष्य की अनिश्चितता। ग्रामीण और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए यह पीड़ा और भी बड़ी है, क्योंकि उनके लिए हर अतिरिक्त महीना आर्थिक दबाव लेकर आता है। यह भी सच है कि इस पूरे श्रष्ट तंत्र को केवल परीक्षा एजेंसी की कमजोरी ने जन्म नहीं दिया। निजी मेडिकल कॉलेजों की करोड़ों की फीस, कोचिंग उद्योग का अरबों का कारोबार और सरकारी सौदों की सीमित संख्या ने एक ऐसा बाजार खड़ा कर दिया है, जहां सफलता को मेहनत से ज्यादा “मैनेजमेंट” से जोड़कर देखा जाने लगा है। जब एक मेडिकल सीट की कीमत करोड़ों में पहुंच जाती है, तब पेपर लीक माफिया के लिए यह सबसे लाभकारी धंधा बन जाता है। पिछले कुछ वर्षों में लगभग हर बड़ी भर्ती और प्रवेश परीक्षा पर सवाल उठे हैं। कभी एसएससी, कभी रेलवे भर्ती, कभी शिक्षक पात्रता परीक्षा और अब नीट। हर बार जांच समितियां बनती हैं, कुछ गिरफ्तारी होती हैं, लेकिन सिस्टम जस का तस बना रहता है। यदि सरकार वास्तव में परीक्षा माफिया को खत्म करना चाहती है, तो उसे केवल निचले स्तर के दलालों को पकड़ने से आगे बढ़ना होगा। उन अधिकारियों, तकनीकी कर्मचारियों और संस्थापक नेटवर्क तक पहुंचना होगा जो इस पूरे खेल को संरक्षण देते हैं। अब समय केवल बयानबाजी का नहीं, कठोर सुधारों का है। परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह विकेंद्रीकृत और पारदर्शी बनाना होगा। प्रश्नपत्र निर्माण से लेकर प्रिंटिंग और वितरण तक हर चरण की स्वतंत्र ऑडिटिंग होनी चाहिए। संवेदनशील जिम्मेदारियों में शामिल कर्मचारियों की जवाबदेही तय हो और दोष सिद्ध होने पर कठोर सजा मिले। साथ ही, परीक्षा प्रणाली को तकनीक पर निर्भर बनाने के साथ-साथ मानव निगरानी और नैतिक जवाबदेही भी मजबूत करनी होगी।

नीट परीक्षा बाल मुकुन्द ओझा



सपने व हौसले तोड़ रहीं पेपर लीक की घटनाएं

देशभर में परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पेपर लीक किसी राज्य विशेष का मामला नहीं है, अपितु यह देश की युवा आबादी के भविष्य से जुड़ा ज्वलंत विषय है। आज प्रतियोगी और भर्ती परीक्षाओं में शुचिता बनाए रखना किसी कठिनतम चुनौती से कम नहीं है। सरकारी नौकरों पाने का सपना हर शिक्षित युवा देखता है। इसके लिए वह सालों तक कड़ी मेहनत और रात दिन पढ़ाई करके परीक्षा में इस उम्मीद और विश्वास से बैठता है कि उसे सफल होना है, लेकिन पेपर लीक की घटनाएं ऐसे अभ्यर्थियों का सपना और हौसला तोड़ देती हैं। पेपर लीक के कारण आयोज्य उम्मीदवार बाजी मार कर शासनतंत्र का हिस्सा बन जाता है। भर्ती परीक्षाओं में सरकारी लापरवाही का खामियाजा बेरोजगारों को वर्षों से भुगतना पड़ रहा है। ताजा प्रकरण नीट यूजी 2026 परीक्षा से जुड़ा सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के आरोपों के बीच राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने 3 मई 2026 को आयोजित नीट-यूजी 2026 परीक्षा को रद्द कर दिया है। केंद्र कैडेट्रेस ने एग्जाम दिया था। राजस्थान के सीकर से नीट यूजी 2026 पेपर लीक का मामला सामने आया है। जांच में सामने आया कि इस गेस पेपर के कई सवाल असली परीक्षा से मिल रहे थे। बताया जा रहा है कि 720 नंबर की परीक्षा में करीब 600 नंबर के सवाल पहले से छात्रों तक पहुंच गए थे। यह कथित क्वेश्चन बैंक एक एमबीबीएस छात्र ने अपने दोस्त को भेजा था, जिसके बाद यह अलग-अलग लोगों तक फैल गया। राजस्थान एसओजी ने इस मामले में एक्शन लेते हुए देहरादून, सीकर और झुंझुनू से 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इससे पूर्व साल 2021 की सब-इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा को राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने माना कि भर्ती प्रक्रिया में बड़े स्तर पर धांधली और सिस्टमेटिक पेपर लीक हुआ था। मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी ओपीएससी के एक सदस्य की गिरफ्तारी भी हुई थी। अब ये परीक्षा दोबारा करवाई जा रही है। इसी बीच नीट पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में भारी हंगामा मच गया है। परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों का गुस्सा और बढ़ गया है। प्रदर्शन और आंदोलन भी शुरू हो गया है। नेताओं ने बयान बाजी शुरू कर दी है। अच्छे भविष्य के लिए लाखों युवाओं के लिए सरकारी नौकरियां किसी सपने से कम नहीं होती। सालों की मेहनत करने के बाद मिलने वाला एक मौका जिनकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन क्या हो जब उनकी मेहनत पर पेपर लीक का दाग लग जाए? पेपर लीक की इस महामारी में सरकारी कर्मचारी शिक्षक अपराधी माफिया, कोचिंग सेंटर, आदि शामिल हैं। विभिन्न प्रदेशों में दर्जनों संपठित गिरोह सक्रीय है जिन्होंने पेपर लीक का ठेका ले रखा है। इन गैंगों ने मोटी राशि वसूलकर पेपर बेचने का आपराधिक कार्य किया। अनेक सरगना और और परिश्रार्थी पुलिस की पकड़ में है जिनसे गहरी पूछताछ की जा रही है। पेपर लीक की समस्या से जुझ रहे कई राज्यों में से राजस्थान भी एक है। राजस्थान में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक होने का सिलसिला कई सालों से चल रहा है। पिछले कांग्रेस शासनकाल में यह कार्य धड़ल्ले से चला। पेपर लीक प्रदेक्ष के युवाओं के लिए अभिशाप बन गया है। इससे न सिर्फ भविष्य निर्माण के कीमती वर्ष बर्बाद हो रहे हैं बल्कि उनके परिवारों पर भी आर्थिक और मानसिक बोझ पड़ रहा है। प्रदेश में पेपर लीक होने की घटनाएं बढ़ती जा रही है। जिस वजह से एग्जाम को रद्द करना पड़ता है और ऐसे छात्रों के भविष्य भी असर पड़ता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इससे पूर्व आएएस भर्ती 2013 में प्री-एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद पता चला कि पेपर पहले ही बाहर था, जिसकी वजह से पूरी परीक्षा रद्द हुई। कार्टेक्ल भर्ती 2018 और 2022 दोनों ही बार पुलिस की अपनी ही परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। जईएन सिविल भर्ती 2020 में पेपर लीक का मामला इतना बड़ा कि बोर्ड के अध्यक्ष को अपने पद से इस्तीफा तक देना पड़ गया था। लाइब्रेरियन भर्ती 2018 में नकल गिरोह के तार शेखावाटी तक फैले मिले और परीक्षा को बीच में ही निरस्त करना पड़ा। एलडीसी भर्ती 2013 में पेपर आउट होने की वजह से जो भर्ती चंद महीनों में होनी थी, उसे पूरा होने में 3 साल लग गए। आरपीएमटी 2014 में सवालों में भारी गड़बड़ी और लीक के आरोपों के बाद इस मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को भी रद्द करना पड़ा था।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार है, ये उनके अपने विचार हैं।)



मंथन

मनोज कुमार अग्रवाल

अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य के अवरुद्ध होने से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट से निपटने में भारत सरकार का कुशल प्रबंधन दुनिया के प्रभावित देशों के लिए एक मिसाल बन गया है, लेकिन मौजूदा समय में अमेरिका और इजराइल-ईरान के बीच जो हालात बने हैं उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि फिलहाल होर्मुज स्ट्रेट मार्ग निर्बाध खुलने की संभावना नहीं है, जिसके चलते सरकार को ऊर्जा संकट से निपटने के लिए मौजूदा संसाधनों की समीक्षा और उर्जा जरूरतों के प्रबंधन की दीर्घकालिक नीति बनानी पड़ रही है। इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी ने आमजन से यह सात सूत्रीय अपील की है। जो देश को ऊर्जा संकट से बचा सकती हैं।

अनासक्त हुए बिना करे दूसरों की भलाई



संकलित दर्शन

यह सोचना भूल है कि हमने संसार का भला किया। इस विचार से दुख उत्पन्न होता है। हम किसी की सहायता करने के बाद सोचते हैं कि वह हमें इसके बदले में धन्यवाद दे, पर वह धन्यवाद नहीं देता, तो हमें दुख होता है। हम जो कुछ भी करें, उसके बदले में किसी चीज की आशा क्यों रखें? बल्कि उल्टे हमें उसी के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, जिसकी हम सहायता करते हैं, उसे साक्षात नाशयण मानना चाहिए। मनुष्य की सहायता द्वारा ईश्वर की उपासना करना क्या हमारा परम सौभाग्य नहीं है? यदि हम वास्तव में अनासक्त हैं, तो हमें यह प्रत्याशा जनक कष्ट क्यों होना चाहिए? अनासक्त होने पर तो हम प्रसन्नतापूर्वक संसार में भलाई कर सकते हैं। अनासक्त किए हुए कार्य से कभी भी दुःख अथवा अशान्ति नहीं आएगी। यदि हम यह जान लें कि आसक्ति रहित होकर किस तरह कर्म करना चाहिए, तभी हम दुराग्रह और मतांधता से परे हो सकते हैं। जब तुम दुराग्रह और मतांधता से परे हो जाओगे, तभी अच्छी तरह कार्य कर सकोगे। जो ठंड मस्तष्क वाला और शांत है, जो उत्तम ढंग से विचार करके कार्य करता है, जिसके मनसुय सहज ही उत्तेजित नहीं होते तथा जो अत्यंत प्रेम और सहानुभूति संपन्न है, केवल वही व्यक्ति संसार में परोपकार कर सकता है और इस तरह वह अपना भी कल्याण कर सकता है। यह संसार चरित्र पठन की एक विशाल व्यायामशाला है। इसमें हम सभी को अभ्यास रूप में कसरत करनी पड़ती है, जिससे हम आध्यात्मिक बल से अधिकाधिक बलवान बनते रहें।

अंतर्मन

आज की पाती

पश्चिम बंगाल में हिंसा क्यों

हाल ही में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव परिणाम आया है, और इसके बाद यहां हिंसा का सिलसिला शुरू हो गया। चुनाव के बाद यहां हिंसा का सिलसिला पुराना है, वर्ष 2011, 18, 19, 21 और अब 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद भी ऐसा हो रहा है। इस हिंसा का कारण कहीं हारे हुए राजनीतिक दलों का बीछलाना तो नहीं? अगर ऐसा है तो यह सरासर गलत है और लोकतंत्र को कलंकित करने वाला है। लेकिन सवाल तो यह है कि इतनी सुरक्षा के बाद भी यहां हिंसा क्यों हो रही है? यहां से समय-समय पर हिंसा की ऐसी खबरे सुर्खियों में आती हैं जो लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा करती हैं, साथ ही वहां की कानून व्यवस्था की भी पोल खोलती हैं। इस हिंसा पर त्वरित रूप से रोक लगनी चाहिए।

- *प्रवीण अग्रवाल, जींद*

करंट अफेयर अब कैमरून करेंगे ‘फेमा’ का नेतृत्व

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कैमरून हैमिल्टन को संघीय आपात प्रबंधन एजेंसी (फेमा) का नेतृत्व करने के लिए नामित किया। पूर्व नौसेना सील हैमिल्टन की यह एक आश्चर्यजनक वापसी है। उन्हें पिछले साल फेमा के अस्तित्व का बचाव करने के बाद इसके कार्यवाहक प्रमुख के पद से बर्खास्त कर दिया गया था। उन्हें नामित करने के साथ ही ट्रंप प्रशासन ने फेमा को भंग करने के अपने वादों से पीछे हटने के संकेत देना शुरू कर दिया है। फेमा एक ऐसी एजेंसी है जिसकी राष्ट्रपति द्वारा कड़ी आलोचना की गई है। हैमिल्टन ने तर्क दिया था कि फेमा को समाप्त करना देश के हित में नहीं है और अब उन्हें नामित किया जाना इस बदलाव के नवीनतम संकेत हैं। हैमिल्टन की नियुक्ति हो जाने के बाद वह ट्रंप और आपात प्रबंधन पर गृह सुरक्षा सचिव मार्कवेन मुलिन के प्रमुख सहाकार होंगे तथा ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में फेमा के पहले स्थायी प्रशासक होंगे। ट्रंप ने सोमवार को ही डेविड कर्मिस को परिवहन सुरक्षा प्रशासन (टीएसए) का प्रमुख नामित किया। कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने के कारण टीएसए को पिछले कुछ महीनों से उथल-पुथल का सामना करना पड़ रहा है और देश भर के हवाई अड्डों पर सुरक्षा कतारें लंबी होती जा रही हैं।



देशभर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हैदराबाद के संबोधन में देशवासियों को ऊर्जा संकट के इस दौर में ऊर्जा सुरक्षा संयमित उपयोग कर कर्तव्य बोध के प्रति जागरूक किया है। पीएम की इस 7 सूत्री अपील में न सिर्फ आम जन के बीच संकट की हालत में मनोबल और विश्वास बने रहने की प्रेरणा है साथ ही संकट से निपटने का मूलमंत्र भी है। सरकार वैश्विक संकट के इस दौर में नागरिकों के लिए सुरक्षा कवच बनकर डूटी रही आयातित तेल पर भारी दाम वृद्धि को सरकार ने 24 से 30 रुपये प्रति लीटर भार वहन किया है पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 13 रुपये से घटित कर तीन रुपये लीटर कर दिया, जबकि डीजल पर उत्पाद शुल्क खत्म कर दिया है। आपको पता है कि अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य के अवरुद्ध होने से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट से निपटने में भारत सरकार का कुशल प्रबंधन दुनिया के प्रभावित देशों के लिए एक मिसाल बन गया है लेकिन मौजूदा समय में अमेरिका और इजराइल-ईरान के बीच जो हालात बने हैं उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि फिलहाल होर्मुज स्ट्रेट मार्ग निर्बाध खुलने की संभावना नहीं है। जिसके चलते सरकार को ऊर्जा संकट से निपटने के लिए मौजूदा संसाधनों की समीक्षा और उर्जा जरूरतों के प्रबंधन की दीर्घकालिक नीति बनानी पड़ रही है पूर्व तक यह अनुमान था कि होरमुज मार्ग का विवाद जल्द सुलझ जाएगा और स्थिति पूर्ववत सामान्य हो जाएगी लेकिन अब ऐसा नहीं है।



भी हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि सवाल यह है कि क्या ‘डिजिटल डिक्टॉक्स’ वास्तव में असरदार है या सेहत की बात करने वाला एक और चलन भर है। इसी तरह डिजिटल डिक्टॉक्स का उद्देश्य तकनीक से कुछ समय के लिए दूरी बनाना। यह अवधारणा ऑनलाइन तेजी से लोकप्रिय हो रही है। इसके समर्थक एनालॉग लाइफस्टाइल के स्वास्थ्य लाभों का प्रचार कर रहे हैं। कुछ लोग बेहतर स्वास्थ्य और खुशी पाने के उद्देश्य से महंगे डिजिटल रिट्रीट कार्यक्रमों में भी हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि सवाल यह है कि क्या ‘डिजिटल डिक्टॉक्स’ वास्तव में असरदार है या सेहत की बात करने वाला एक और चलन भर है। इसी तरह डिजिटल डिक्टॉक्स का उद्देश्य तकनीक से कुछ समय के लिए दूरी बनाना, कम व्यवधानों के साथ जीवन का अनुभव करना और ऑफलाइन रिश्तों को मजबूत करना है। ऑस्ट्रेलिया में युवा औसतन रोजाना नौ घंटे स्क्रीन देखते हैं। शोध बताते हैं कि वयस्क भी इससे बहुत पीछे नहीं हैं। 45 से 64 वर्ष आयु वर्ग के ऑस्ट्रेलियाई प्रतिदिन करीब छह घंटे स्क्रीन पर बिताते हैं।

नाजुक वक्त में काबिले गौर है पीएम की सलाह

स्कूल बंद जैसे अनेक प्रतिबंध भरे कदम उठाए लेकिन भारत सरकार की सूझ-बूझ और प्लानिंग के चलते ईंधन राशनिंग नहीं हुई, स्कूल बसों, वाहनों व परिवहन यातायात की गाड़ियों को मांग के अनुरूप फ्यूल मिलते रहने से कोई स्कूल बंदी नहीं हुई और न ही कोई दफ्तर बन्द करने पड़े। तमाम दफ्तर सामान्य तौर पर कार्यरत रहे जिससे कोई बर्क-फ्रॉम-होम निर्देश पारित करने की नौबत नहीं आने पाई। देश भर में खुदरा ईंधन की स्थिर आपूर्ति बनाए रखी गई। यह सब त्वरित सरकारी हस्तक्षेप से संभव हो पाया है। एलपीजी और घरेलू आपूर्ति संरक्षण व्यवधान के 8 दिनों के भीतर सरकार ने एलपीजी नियंत्रण आदेश जारी किया रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन अधिकतम करने का निर्देश दिया गया। घरेलू



एलपीजी उत्पादन को 36,000 टन प्रति दिन से बढ़ाकर 54,000 टन प्रतिदिन कर दिया गया जो लगभग 50 फीसद की वृद्धि है। 9 दिनों के भीतर प्राकृतिक गैस आपूर्ति विनियमन आदेश जारी किया गया। पीएनजी घरेलू उपभोक्ताओं और सीएनजी सार्वजनिक परिवहन को 100 फीसदी आवंटन के साथ संरक्षित किया गया। सरकार द्वारा सार्वजनिक आपूर्ति बनाए रखने के लिए औद्योगिक आवंटन को भी सुचारू और युक्तिसंगत बनाए रखा। भारत सरकार द्वारा रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिम बंगाल, अफ्रीका, अटलांटिक बेसिन से त्वरित संपर्क स्थापित कर ईंधन आपूर्ति की व्यवस्था की गई। भारत में एलपीजी की मांग लगभग 90,000 टन की प्रतिदिन की रह गई है। सरकार द्वारा आठ लाख टन कागों पहले ही सुरक्षित किए जा चुके हैं, जिससे आज हमारे पास चालीस दिनों का अंतिम भंडार उपलब्ध है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती घरेलू रसोई गैस की निर्बाध

आपूर्ति सुनिश्चित करना था। इस कठिन समय में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा की गई पहल के तहत, सरकार ने पनामा नहर जैसे वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करते हुए अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया और पश्चिम अफ्रीका से तेल और गैस आयात के लिए वैकल्पिक इंतजाम किए। इसके साथ ही, सरकार ने देश के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का बुद्धिमानी से उपयोग किया, जो भारत को अल्पावधि के लिए वैश्विक आपूर्ति झटकों से बचाते हैं। सरकार के इस कदम ने न केवल बाजार को स्थिरता प्रदान की, बल्कि ईंधन की कीमतों में अत्यधिक उछाल को रोकने में भी मदद की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भारत ने पश्चिम एशियाई देशों, विशेषकर सऊदी अरब, यूएई और ईरान के साथ निरंतर कूटनीतिक संवाद बनाए रखा इस के चलते होर्मुज संकट के बावजूद भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही बनी रही। भारत की कूटनीतिक सक्रियता का ही परिणाम था कि ईरान ने सशत रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य को खुला रखने पर सहमति व्यक्त की, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति में पूरी तरह से ठहराव की स्थिति टल गई। संकट काल में सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा के मोर्चे पर भी बड़ी सफलता हासिल की। भारत ने 2030 के लक्ष्य से पहले ही, 2026 में अपनी गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से स्थापित बिजली क्षमता का 50 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया। यह न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम कर ऊर्जा सुरक्षा की दीर्घकालिक मजबूती प्रदान करता है। सरकार को देश की प्रगति यानी जीडीपी की रफ्तार की गति बनाये रखने के लिए किसी दीर्घकालिक रणनीति के अवलम्बन की आवश्यकता होती होगी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा विशेषी मुद्रा और आर्थिक संकट से निपटने के लिए देशवासियों से कई महत्वपूर्ण अपीलों कीं। मौजूदा संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने मुख्य सुझाव दिया है। पीएम ने नागरिकों से पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने और सार्वजनिक परिवहन मैट्रो सिटी बस या इलेक्ट्रिक वाहनों का अधिक उपयोग करने को कहा।विदेशी मुद्रा भंडार बचाने के लिए, पीएम ने देशवासियों से कम से कम एक साल तक सोना न खरीदने की अपील की।उन्होंने कोरोनाकाल की तरह ही 'वर्क फ्रॉम होम' की व्यवस्था फिर से अपनाने को कहा, ताकि यात्रा कम हो और ईंधन बचे। यह न सिर्फ जरूरी है वरन देश के हर नागरिक को सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संकट से निपटने का संकल्प भी पैदा करने का प्रयास है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार है, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

दो अनमोल हीरे

एक व्यापारी को बाजार में घूमते हुए एक बहुत अच्छी नरसल का ऊंट दिखाई पड़ा। व्यापारीव्यापारी ऊंट खरीद कर घर ले आया। घर पहुँचने पर व्यापारी ने अपने नौकर को ऊंट का कजावा (काठी) निकालने के लिए बुलाया। कजावे के नीचे नौकर को एक छोटी सी मखमल की थैली मिली जिसे खोलने पर उसे कीमती हीरे जवाहरात भरे होने का पता चला।। नौकर चिल्लाया, मालिक आपने ऊंट खरीदा, लेकिन देखो, इसके साथ क्या मुभ्त में आया है। व्यापारी बोला- मैंने ऊंट खरीदा है, न कि हीरे, मुझे उसे तुरंत वापस करना चाहिए। नौकर बोला- मालिक किसी को पता नहीं चलेगा। पर, व्यापारी ने एक न सुनी और वह तुरंत बाजार पहुँचा और दुकानदार को मखमली थैली वापिस दे दी। ऊंट बेचने वाला बहुत खुश था। अब आप इनाम के तौर पर कोई भी एक हीरा चुन लीजिए। व्यापारी बोला- मैंने ऊंट के लिए सही कीमत चुकाई है इसलिए मुझे किसी शुक्राने और उपहार की जरूरत नहीं है। अंत में व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा- जब मैंने थैली वापस लाने का सोचा तो मैंने पहले से ही दो सबसे कीमती हीरे इसमें से अपने पास रख लिए थे। इस कबूलनामे के बाद ऊंट बेचने वाला भड़क गया उसने अपने हीरे जवाहरात गिनने के लिए थैली को तुरंत खाली कर लिया। पर वह था बड़ी पशोपेश में बोला- मेरे सारे हीरे तो यहीं हैं, तो सबसे कीमती दो कौन से थे जो आपने रख लिए? व्यापारी बोला- मेरी ईमानदारी और मेरा आत्म सम्मान। जिस-जिस के पास वह 2 हीरे है वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं।

हिमंत व मंत्रियों को शुभकामनाएं

मैं असम के मुख्यमंत्री का पदभार हाथ कचरे पर हिमंत विश्व सरमा को और मंत्रियों के रूप में शाध हाथ कचरे पर जगदेव तेली, अतुल बोरा, वराण बोरो और अजंता निरवो को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। गाजा की डबल इंजन की सरकार असम के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेगी।

-**जोषी नandu**, केंद्रीय मंत्री

य्वाओं के सपने क़चले

नीट 2026 की परी़ा रट हो गई। 22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग व सपनों को इस ग़द गाजापई व्यवस्था ने कुचल दिया। लाखों बच्चों ने रात-रात भर जागकर पढ़ाई की और बचले में मिलान-पेपर लीक, सटकारी लापरवाही व शिक्षा में संगठित बढावादा। -**राहुल गांधी**, कांग्रेस सांसद

विश्वास पर बड़ा आघात

जब परीक्षाओ की शुचिता से समझौता होता है, तो यह केवल एक फूक नहीं, बल्कि उन लाखों अभ्यर्थियों के साथ विश्वासघात है जिन्होंने अनुशासन के साथ पढ़ाई की, सुख-सुविधाओं का त्याग किया और तैयारी के लिए रातों की नींद गंवाई।

-**नवीन पटनायक**, नेता प्रतिपक्ष, ओडिशा

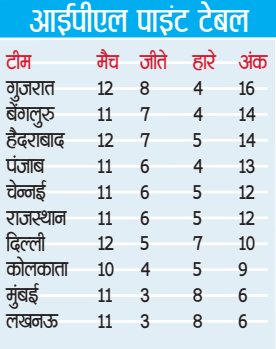
निजी स्कूल मनमानी न करें

निजी स्कूलों को फीस संरचना का पूरा विवरण सार्वजनिक करना होगा। फीस और अन्य शुल्कों में मनमानी तथा अनुचित वृद्धि पर पूरी तरह रोक रहेगी। अभिभावकों को पेशानी नहीं आने दी जाएगी। वंदी और किताब किसी भी दुकान से खरीद सकेंगे।

-**सयाद चौधरी**, सीएम बिहार

हमारा पता

हरिभूमि कार्यालय
नजदीक इंडस पब्लिक स्कूल, दिल्ली रोड, रोहतक-124001 फोन- 9253681019-20 ई-मेल - haribhoomi@gmail.com वेब-साइट - www.haribhoomi.com



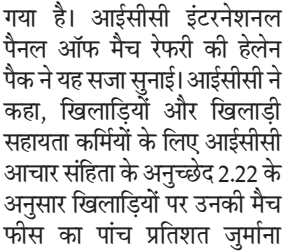
**विरोध प्रदर्शन के कारण
हुआ नुकसान : पूनिया**

लक्ष्य फाइनल में, चार मुक्केबाजों को कांस्य
ताशकंद। भारत के लिये एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैम्पियनशि में मंगलवार का दिन चुनौतीपूर्ण रहा जब लक्ष्य फोगाट अनेकौ फाइनल में पहुंचे जबकि चार अन्य मुक्केबाजों को सेमीफाइनल में हारने के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। 75 किलोग्राम में लक्ष्य ने कोरिया के सियुंगमिन ली को 5.0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में नरेंद्र नेल्ला (46 किलो) को उजबेकिस्तान के अब्दुल्लाह नुरालीव ने 5.0 से हराया। यश यादव (50 किलो) को मंगोलिया के एस उसुखबातर ने 4.1 से मात दी जबकि निशेथ पाल 54 किलोग्राम में उजबेकिस्तान के अब्दुलबोसित सुयुनबोवोव से 5.0 से हार गए। नमन (70 किलो) को उजबेकिस्तान के अब्दुवोहिद अब्दुमाजिदोव ने 3.2 से हराया।

विश्व कप 12 जून से 5 जुलाई तक इंग्लैंड में खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका ग्रुप 1 में शामिल है। इस ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भारत, नीदरलैंड, और पाकिस्तान शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका 13 जून को मैचवेस्टर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा।

शबानम हुसैनलाल को दक्षिण अफ्रीका टीम में जगह देने की कई वजहें थीं। पहला, इस्महिला बैथक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल रही हैं। लेकिन दुनिया की बड़ी लीग में लगातार सक्रिय हैं। वह संन्यास के बाद से महिला विश्व बैथक लीग, महिला ट्वेन्टिथ प्रिमीयर लीग और महिला ट्वेन्टिथ प्रिमीयर टी-20 में खेल रही हैं। इस वजह से उनके पास फॉर्म और फिटनेस दोनों हैं। दूसरा, वह दक्षिण अफ्रीका की सुफन और बेहतर टीम तेज गेंदबाज रह चुकी हैं। उन्होंने 113 मैचों में 122 विकेट लिए हैं। विषय का इस्तेमाल में उन्हें वापस है। वहां शबानम की गति और अनुभव टीम के काम का सकता है। इसी वजह से दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें संन्यास से वापसी कराते हुए टीम में जगह दी है।

फेंकने की गति धीमी रही। इस वजह से टीम पर जुर्माना लगाया गया है। समय की छूट को ध्यान में रखने के बाद अमेरिलिया केर की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड एक ओवर पीछे रह गई थी। इस वजह से टीम पर मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया



लगाया जाता है। यह हर उस ओवर के लिए जो उनकी टीम निर्धारित समय में नहीं फेंक पाती है। न्यूजीलैंड की टीम निर्धारित समय पर एक ओवर पीछे रही थी, इसलिए 5 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। कप्तान केर ने अपराध स्वीकार कर लिया और प्रस्तावित सजा मान ली।

सनराइजर्स को हराकर लगातार पांचवीं जीत के साथ गुजरात टाइटंस शीर्ष पर



खिलाड़ी	रन
शुभास सुदर्शन का हिनें बो हुयेन	61
सहमान विल का वलाने बो हुिये	5
जिसे बटकर का ईशान को हिनें	77
निशित का वलाने बो कमिस	22
सुंदर का ईशान को साकिब	50
जैसन होल्डर नाबाद	4
राहुल तेवतिया नाबाद	11
अतिरिक्त : चार रन	
योग : 20 ओवर में पांच विकेट पर	
168 रन	
विकेट पतन : 1-15, 2-26, 3-64, 4-124,	
5-164	
गेन्दबाजी: कमिस 4-0-20-1, रेडी 3-0-0-	
27-20, हिनें 3-0-17-2, मलिंगा 4-0-16-	
0, हुसेन 4-0-37-2, शिवांग 2-0-19-0	

खिलाडी	०
रेसिंग हेड का सिंथो बो सिराज	२
अभिषेक शर्मा बो रेखाड	१
इंशान का बटलर बो रेखाड	6
रेविन्द्रका का लालो बो रेखाड	9
वल्लभन का बटलर बो होल्डर	14
सुनिल का बटलर बो कृष्ण	1
नीतिश रेडी का सुंदर बो होल्डर	2
टु कमिंस का सिराज बो कृष्ण	19
शुभांग का बटलर बो होल्डर	4
पुष्पल टु बटलर बो राशिश	3
एशान मलिंगा नाबाद	0
अतिरिक्त : दो नंबर	
१५-१५ ओवर में ८६ रन	
विजेट पान : 1-0, 2-6, 3-23, 4-32,	
5-56, 6-56, 7-60, 8-72, 9-82	
देवाडी : सिराज 3-11-11, रेखाड	
4-0-28-3, होल्डर 4-0-20-3, कृष्ण	
3-0-23-2, सिराज 0-5-0-3-1	

रहस्यपूर्ण। प्लेऑफ की दहलीज पर खड़ी रॉयल वेल्डर्स बेल्गियम (आरसीबी) की टीम को अगर अंतिम चार में अपनी जगह लगाने (निर्देशांक) में वे तो उसके बल्लेबाजों की बुधवार को कोलकाता नाइट राइडर्स (केनकेआर) के कर्नलों के सामने आकामक प्रदर्शन करना होगा। आरसीबी फिलहाल 14 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर है। लेकिन मंगलवार को होने वाले मैच के बाद इस स्थान पर सनराइजर्स हैदराबाद या गुजरात टाइटन्स काबिजा हो जाएंगे, जिनके पास भी 14 अंक हैं। आरसीबी ने अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन पिछले कुछ मैच में उसके बल्लेबाज अपेक्षित खेल नहीं दिखा पाए। मुईउद्दीन अली के खिलाफ पिछले मैच में 167 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए उसकी बल्लेबाजी लड़खड़ा गई थी और उसने बमुश्किल जनी हासिल की थी। उसकी टीम अगर फिर से इस तरह की परिस्थिति में नहीं गुजरना चाहेगी।

धर्मशाला। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल पर इंडियन प्रीमियर लीग में पंजाब किंग्स के खिलाफ अपनी टीम की जीत के लिए 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अक्षर और डेविड मेल्टर के अर्धशतकों की मदद से दिल्ली कैपिटल्स ने इस मैच में पंजाब किंग्स को तीन विकेट से हराकर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी आखिरी उम्मीदों को बरकरार रखा। आईपीएल के अनुसार, 'दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल पर महाराष्ट्र प्रदेश क्रिकेट संघ स्टैडियम, धर्मशाला में पंजाब किंग्स के खिलाफ आईपीएल के मैच के दौरान धीमी ओवर गति बनाए रखने के लिए जुर्माना लगाया गया है।' इसमें अर्ग काहा गया है, 'धीमी ओवर गति से संबंधित आईपीएल की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के तहत यह उनकी टीम का इस सत्र का पहला अपराध था। इसलिए अक्षर पटेल पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।' दिल्ली की टीम अंक तालिका में अभी सातवें स्थान पर है। उसका अगला मैच रविवार को नई दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ होगा।

बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट मैच को 104 रन से अपने नाम किया। दोनों पारियों में शानदार बल्लेबाजी के लिए बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हुसैन शांतो को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।

इस जीत के साथ मेजबान टीम ने दो मुक़ाबलों का सीराज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है। सीराज का अगला मैच 16 मई से सिलहट में खेला जाएगा। बांग्लादेश के पाहली मई के आधार पर 27 रन की बढ़त थी। अगली पारी में मेजबान टीम ने 9 विकेट खोकर 240 रन बनाए और पाकिस्तान को जीत के लिए 268 रन का लक्ष्य दिया। बांग्लादेश की तरफ से इस पारी में कप्तान नजमुल ने सर्वाधिक 87 रन बनाए, जबकि मोमिनुल हक ने 56 रन और योगदान दिया। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तानी टीम दूसरी पारी में महज 163 रन पर सिमट गई।



मुकालेमें टीएम गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी बांग्लादेशी टीम पहली बार में 413 रन पर सिमट गइल। इस पारी में कप्तान नजमुल हuseन ने 2 शतकों और 12 चौकों के साथ 101 रन की पारी खेली, जबकि मोमिनूल हक ने 91 रन टीम के खाते में जोड़े। मुशफिकुर रहमान ने 71 रन का योगदान दिया। विपक्षी खेमे से मोहम्मद अब्बास ने सर्वाधिक 5 विकेट हासिल किए, जबकि शाहीन अफरिदी ने 3 विकेट निकाले। हसन अली और नोमान अली को 1-1 विकेट हाथ लगा।

खिलाड़ियों के हक की लड़ाई में आगे आई जैसिका



पेगुला ने कहा, मुझे लगता है कि यह शायद स्वाभाविक रूप से हो जाता है क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने इसमें कुछ दृढ़ तत्व नेतृत्व की भूमिका निभाई है। पेगुला को इस साल महिला जेनिंस कैलेंडर, सैकिक अंकों के नियमों और कुछ स्थानों में भाग लेने की योग्यता तय करने के लिए गठित किए गए 17-दस-सदस्यीय पैनल का नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया था। अब वह पुरस्कार राशि के मुद्दे पर भी काम कर रही हैं।

पेगलु ने कहा, 'मुझे किसी भी खिलाड़ी के पास जाकर यह पूछने में कोई झिझक नहीं है कि' क्या आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं या नहीं।' कुछ क्षणों के पश्चात वह मुझे भी हँसी और इसका लेकर चिंतित नहीं होने। कभी-कभी वे कहते हैं, 'हां, मैं पूरी तरह से तैयार हूं।' मैं पुरुष और महिला दोनों वर्ग के खिलाड़ियों से संपर्क कर रही हूं।

खिलाड़ियों की मांग महत्वपूर्ण

पेगलु ने कहा, 'आखिर मैं खिलाड़ियों की मांग महत्वपूर्ण होती है। परीना और यानिक को इस मामले में खुलकर बोलते हुए देहना अच्छा लगता। मैं जानती हूँ कि कई अन्य खिलाड़ी भी ऐसा ही महसूस करते हैं। लेकिन जब विश्व के दोनों बंबर एक खिलाड़ी इस पर खुलकर बोलते हैं, तो उनको बात सुनने की इच्छा होती है। एनएफएल और एनएचएल में खिलाड़ियों को राजस्व का लगभग 50 प्रतिशत मिलता है वहीं अधिकतर ओएस प्रतियोगिताओं में यह आंकड़ा इससे तैयार से भी कम है। खिलाड़ियों ने पिछले सप्ताह को बयान जारी किया था उसके अनुसार प्रेच ओपन में महत्वपूर्ण को कथित तौर पर 14.9 प्रतिशत से भी कम हिस्सा दिया जा रहा है।

■ खिलाड़ियों को कर रही एकजुट

की पुरस्कार राशि बढ़ाने के अभियान को जिसका पेंगुला का भी समर्थन मिला है, जो खिलाड़ियों को इस मामले में एकजुट करने की भूमिका निभा रही हैं। यूएस ओपन 2024 की उपविजेता पेंगुला के लिए यह व्यक्तिगत है, क्योंकि वह खेल प्रबंधकों के परिवार में पली-बढ़ी हैं। उनके माता-पिता एनएफएल की बंफेलो बिस्त्स और एनएचएल की बंफेलो सेन्स के मालिक हैं।

चालीं डीन और अमेलिया केर ने लगाई लंबी छलांग



इंग्लैंड की चार्ली डीन और न्यूजीलैंड की कप्तान अमेलिया केर को वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में शानदार प्रदर्शन का इनाम आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में मिला है। इंग्लैंड टीम की कप्तानी संभाल रही चार्ली डीन ने पहले वनडे में बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने बल्लेबाजी में 46 गेंदों में



31 रनों की दमदार पारी खेली और वह टीम को जीत दिलाकर लीग में वहीं, गेंदबाजी में उन्होंने 7 ओवर के स्पेल में महज 21 रन खर्च करके हुए 2 विकेट चटकाए। गेंदबाजी की रैंकिंग में डीन अब छह पायदान की छांटांग लगाकर 10वें नंबर पर आ गई हैं। वहीं, ऑलराउंडर्स की लिस्ट में भी उनको एक पायदान का फायदा पहुंचा है और वह अब 11वें स्थान पर आ गई हैं।

अमरिया कर और उनको टीम की साथी खिलाड़ी मैडी ग्रीन न वनडे में बल्लेबाजों की ताजा रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई है। पहले वनडे में 88 रनों की पारी खेलने वाली ग्रीन दो पायदान ऊपर चढ़कर सातवें नंबर पर पहुंच गई हैं। वहीं, अधस्तनशायी पारी के बूते केर ने चार पायदान की छलांग लगाई है और वह अब 11वें नंबर पर आ गई है।

सुखी निविदा सुचना से : टीआरडी-11.05.2021 से
 2026-27-05, दिनांक:- 12.06.2021, राशि
 मंडल विद्युत निगम (एनडीएल) टीआरडी, पूर्व लेख,
 आसमाल मंडल, इंदौर, रीवा, डा. आसमाल, पिन-
 713301 द्वारा स्वायत्तगण निविदाकारों निविदा
 प्राप्त एवं विद्युत ऊर्जाक व लाईसेंस एवं सुचारुआय
 लाईसेंस हेतु और निम्नलिखित कार्य का करने में
 विनियम कर सम्मेलन है, ये से-निविदा आमंत्रित
 की जाती है। निविदा करने से, टीआरडी-डब्ल्यूसीटी
 टी-2026-27-05, कार्य का नाम: आसमाल मंडल
 मंडल: एनटी-कक्षाविधि डिवाइस, एनटी-बर्ड डिस्क,
 डबल कॉन्टैक्ट बयार आदि के प्राधान्य
 द्वारा ओपेराटिंग की विश्वनीयता का सुचारु एवं अन्य
 विश्वनीयता सुधार के उपान। निविदा मुद्रा:-
 ₹. 4,14,10,029.94, बयाना राशि:-
 ₹. 8,28,200/-, कार्य की समापन अवधि:-
 स्वीकृत पत्र जारी होने की तिथि से 12 (बारह)
 माह। कार्य के लिए प्रत्येक की वेधना: खुलने की
 तिथि से 60 दिन। खुलने की तिथि और समय:-
 दिनांक 12.06.2026 को 15.00 बजे। संपूर्ण
 विवरण लेखों की वेबसाइट: www.ireps.gov.in
 में देखा जा सकता है।

इ-नालामा सूचन

क्र०	नीलामी केटलाग सं.	नीलामी शुरू होने की तिनाक एफ समय	नीलामी समाप्त होने की तिनाक एफ समय
1.	UMB-SLR05-A2026 (08 लॉट)	20.05.2026/12:00	20.05.2026/13:40
क्र०	ट्रेन सं०	से-तक	कम्पार्टमेंट
1.	15744	BTI-BLGT	RSRL-I
2.	12418	CDG-PYGS	FSLR-I
3.	20990	CDG-UDZ	FSLR-I
4.	22710	AADR-NLI	FSLR-I
5.	14522	UMB-DL1	FSLR-I
6.	19308	UHL-INDB	FSLR-I
7.	22686	CDG-YPR	RSRL-I
8.	14218	CDG-PYGS	RSRL-I

ई-नीलामी में भाग लेने या ई-नीलामी प्रक्रिया से संबंधित किसी भी अन्य जानकारी के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को www.ireps.gov.in वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

